www.summerexpress.in

द समर न्यूज़

समर एक्सप्रेस

सूर्योदय सुबह 5:33 बजे
सूर्यास्त शाम 7:26 बजे

R.N.I NO. CHMUL/25/A1155

• साल-1 • अंक-316 • पृष्ठ-8 • मूल्य-5 रूपये • सोमवार 20, जुलाई 2026 • चंडीगढ़ • पंजाब • हरियाणा • हिमाचल • ग्रुप एडिटर : अर्शदीप सिंह समर • एग्जीक्यूटिव एडिटर : नितिन उपमन्यु

न्यूज़ ब्रीफ

यूक्रेन ड्रोन हमले में 9 मरे, 80 घायल

मास्को| यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस हमले में नौ लोगों की मौत हुई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूसी अधिकारियों के मुताबिक, यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की प्रमुख ऑनलाइन कंपनी वाइल्डबेरीज के दो बड़े गोदामों को निशाना बनाया। इनमें से एक गोदाम मॉस्को के पास एलेक्ट्रोस्टाल शहर में और दूसरा तांबोव क्षेत्र के कोतोव्स्क में स्थित था। इसके अलावा, मॉस्को क्षेत्र के नोगिंस्क शहर में एक तेल डिपो को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिससे आग लग गई। आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूक्रेन, रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करने के लिए लगातार हमला कर रहा है।

अमरीका ने ईरान पर किए नए हवाई हमले

वाशिंगटन| अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले किए हैं। अमरीकी सेना के मुताबिक, ये कार्रवाई ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के खिलाफ की गई है। यह हमला जॉर्डन में हुए उस हमले के जवाब में किया गया, जिसमें दो अमरीकी सैनिकों की मौत हो गई, एक सैनिक लापता है और चार अन्य घायल हुए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों के आवागमन को प्रतिबंधित करने की ईरान की क्षमता को नुकसान पहुंचाना है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की करीब 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति के लिए एक अहम समुद्री मार्ग है।

राजौरी जिले में बस स्टैंड का मिटा नामोनिशान, बह गये सैंकड़ो वाहन

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन और बाढ़ में 11 की मौत, दर्जनों लापता

बस स्टैंड का मिटा नामो-निशान, बह गईं 250 कारें

राजौरी जिले में बाढ़ का मंजर बेहद खौफनाक रहा। तड़के करीब 3 बजे आई बाढ़ ने बेला बस स्टैंड के निचले इलाके को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। स्थानीय निवासियों के अनुसार, देखते ही देखते 200 से 250 कारें पानी के तेज बहाव में बह गईं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कारों को खिलौनों की तरह बहते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब बस स्टैंड का कोई निशान तक बाकी नहीं बचा है और दो मकान भी पूरी तरह बह गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लगातार वर्षा और अचानक आई बाढ़ के बाद राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों को सभी प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आपातकालीन टीमें किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें।मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी।

समर न्यूज़ | जम्मू

जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में प्रकृति ने विनाशकारी रूप धारण कर लिया है। रविवार को हुई मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पूरे इलाके में भारी तबाही मचाई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस आपदा में 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन, सेना और आपदा प्रबंधन की टीमें युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। बाढ़ का सबसे घातक प्रभाव पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में देखने को मिला है, जहां खराब मौसम और फ्लैश फ्लड के कारण 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राजौरी में भी बाढ़ की चपेट में आने से एक महिला ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। अधिकतर मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सुरनकोट तहसील से हुई हैं। यहाँ प्रशासन ने फँसे हुए लोगों तक पहुंचने, प्रभावित इलाकों को साफ़ करने और प्रभावित लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए बचाव दल तैनात किए हैं और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। पुंछ के नूनाबंदी गाँव में घर ढहने से एक 28 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उसके पति और तीन बच्चों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुँचाया गया है। लोअर मुराह गाँव में एक मकान पर चट्टान गिरने से मकान-मालिक और परिवार के पाँच अन्य सदस्य लापता हो गए। मरहोट गाँव में एक लड़की नाले में डूब गई, जबकि जिले में धुंडक लाथूंग पुल के पास नाले से एक अज्ञात महिला का शव निकाला गया। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, कई रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से लोग फंस गए थे। भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं।

सनप्रीत ने डेढ़ मिनट में सजाई पीएम मोदी के सिर पर पगड़ी

समर न्यूज़ | जालंधर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनके सिर पर नजर आई हरे रंग की पगड़ी जालंधर के पगड़ी प्रशिक्षक सनप्रीत सिंह ने सजाई थी। यह तीसरा अवसर था, जब सनप्रीत को प्रधानमंत्री मोदी को पगड़ी बांधने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने करीब डेढ़ मिनट में छह मीटर कपड़े से सेमी पटियाला शाही शैली की पगड़ी तैयार की। सनप्रीत ने बताया कि उन्हें कार्यक्रम से एक दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से सूचना मिली थी। उन्हें विशेष रूप से हरे रंग का पगड़ी का कपड़ा साथ लाने के लिए कहा गया। पुलिस सत्यापन और सुरक्षा प्रक्रिया की जल्दबाजी में वह पगड़ी के नीचे बांधी जाने वाली 'फिफ्टी' यानी पटका लाना भूल गए थे। बाद में इसे समय रहते मौके पर मंगवा लिया गया। प्रधानमंत्री को पगड़ी बांधने के लिए सनप्रीत को करीब दो मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर दिया। पगड़ी बांधने के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों ने कपड़े का छोर पकड़ने में उनकी सहायता की। सनप्रीत ने बताया कि प्रधानमंत्री के सामने होने के कारण उन्हें थोड़ी घबराहट थी। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पगड़ी ज्यादा कसकर न बंधे और प्रधानमंत्री सहज महसूस करें। सनप्रीत के अनुसार, प्रधानमंत्री ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि पगड़ी पिछली बार से बेहतर और थोड़ी छोटी बांधनी है। पगड़ी तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री ने शीशे में खुद को देखा और इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि पगड़ी बहुत सुंदर बांधी गई है। सनप्रीत ने उनसे पूछा कि पगड़ी ज्यादा टाइट तो नहीं है, जिस पर प्रधानमंत्री ने इसे बिल्कुल ठीक बताया और उनसे हाथ भी मिलाया। इस बार पगड़ी के लिए छह मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया गया। पिछली बार करीब साढ़े छह मीटर कपड़ा इस्तेमाल होने के कारण पगड़ी कुछ भारी हो गई थी। इस बार आखिरी लड़ को मोरनी शैली देने के बजाय सीधा और साधारण रखा गया। इससे पहले सनप्रीत प्रधानमंत्री को दो बार केसरी रंग की पगड़ी बांध चुके हैं। सनप्रीत ने बताया कि सुरक्षा कारणों से उन्हें मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी।

मुख्यमंत्री मान ने बैडमिंटन हॉल के निर्माण के लिए दी 2.14 करोड़ की ग्रांट

समर न्यूज़ | जालंधर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को ऐतिहासिक राजकीय हंसराज बैडमिंटन स्टेडियम का दौरा कर दिसंबर में होने वाली सब-जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्टेडियम में अत्याधुनिक इंडोर बैडमिंटन हॉल के निर्माण के लिए 2.14 करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट देने की घोषणा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 44 वर्षों के बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप राजकीय हंसराज स्टेडियम में लौट रही है। अंडर-13 वर्ग की यह प्रतियोगिता पंजाब में बैडमिंटन को बढ़ावा देने के साथ राज्य की खेल संस्कृति को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए खेलों और आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास पर लगातार जोर दे रही है। भगवंत मान ने 2.14 करोड़ रुपये की मंजूरी का चेक जालंधर के डिप्टी कमिश्नर वरजीत सिंह वालिया और पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव रितिन खन्ना को सौंपा। उन्होंने कहा कि करीब छह दशकों में यह पहला अवसर है, जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस प्रतिष्ठित स्टेडियम का दौरा किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, परियोजना का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा और टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। निर्माण कार्य अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। स्टेडियम में मौजूद चार आउटडोर बहुउद्देश्यीय कोर्टों को अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली इंडोर बैडमिंटन सुविधा में बदला जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद स्टेडियम में कुल 10 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही यह पंजाब का सबसे बड़ा इंडोर बैडमिंटन परिसर और उत्तर भारत के प्रमुख बैडमिंटन केंद्रों में से एक बन जाएगा। इससे राज्य की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने की क्षमता भी बढ़ेगी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल अधिकारियों से बातचीत की तथा मौजूदा सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया।

राजीव दत्ता ने की घोषणा: देशभर के पत्रकारों को जेपीएल में खेलने के लिए किया जाएगा आमंत्रित

जयपुर में होगा अगला जेपीएल: राजीव दत्ता

समर न्यूज़ | जयपुर

जयपुर स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के आयोजन पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी एवं राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों ने उनके समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं और मांगें रखीं। बैठक में मई 2026 में चंडीगढ़ में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग की सफलता की भी सराहना की गई, जिसमें राजस्थान के पत्रकारों की टीम ने खिताब अपने नाम किया था। राजीव दत्ता ने घोषणा की कि जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग का अगला संस्करण जयपुर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देशभर से पत्रकारों की टीमों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों को खेल के माध्यम से एक साझा मंच मिल सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल पत्रकारों के बीच आपसी भाईचारा और सहयोग बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में खेल, फिटनेस और सकारात्मक जीवनशैली का संदेश भी देते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का कार्य अत्यंत जिम्मेदारी और मानसिक दबाव से जुड़ा होता है। ऐसे में खेल गतिविधियां पत्रकारों को तनावमुक्त रखने, शारीरिक रूप से सक्रिय बनाने और आपसी संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जयपुर में होने वाली लीग युवाओं को खेलों से जुड़ने और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करेगी।बैठक के दौरान राजीव दत्ता ने उपस्थित पत्रकारों को संघ की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया। पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के अध्यक्ष मुकेश मीणा ने राजीव दत्ता का स्वागत करते हुए कहा कि जयपुर में जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग आयोजित कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि राजीव दत्ता के सहयोग से इस बार लीग को बड़े और व्यवस्थित स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आयोजन स्थल, टीमों की भागीदारी, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जल्द विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। प्रेस क्लब के महासचिव राज कुमार शर्मा ने कहा कि जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण में राजस्थान की टीम की जीत से राज्य के पत्रकारों का मनोबल भी मजबूत हुआ है। आगामी जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के जयपुर में आयोजन की घोषणा से पत्रकारों में नया जोश है। बैठक के दौरान पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा, जरनल सेक्रेटरी राज कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष नमो नारायण अवस्थी, उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, मुकेश चौधरी, निखलेश शर्मा, हरीश गुप्ता, विजेंद्र जयसवाल विक्की और यूनाइटेड प्रेस कल्ब के प्रधान अर्शदीप समर समेत अन्य पत्रकार मौजूद थे।

जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग-2026 में राजस्थान बना चैंपियन

जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से यूनाइटेड प्रेस क्लब के सहयोग से आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग-2026 में देश के आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पत्रकार टीमों ने हिस्सा लिया था। शहीद पत्रकारों को समर्पित यह प्रतियोगिता 10 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित की गई। चंडीगढ़ के सेक्टर-16 क्रिकेट स्टेडियम में कई प्रमुख मुकाबले खेले गए, जबकि ग्रैंड फिनाले पंचकूला में हुआ। प्रतियोगिता में राजस्थान के पत्रकारों की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया।

सिटीजन रिपोर्टर

अब आप भी बन सकते हैं समर एक्सप्रेस के सिटीजन रिपोर्टर। अपने इलाके की कोई भी समस्या, आयोजन, जानकारी या खबर हमें भेजें। आपके नाम के साथ प्रकाशित की जाएगी। अपनी खबर इस फोन नंबर 8699221114 या ईमेल infosummerexpress@gmail.com पर भेजें।

BOOK YOUR ADVERTISEMENT

If you want to publish your advertisement on our newspaper

समर एक्सप्रेस

CONTACT:
+91 6283 860 059

एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने पर विपक्ष का सांकेतिक विरोध

मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित

एजेंसी | नई दिल्ली

सामाजि संसद के मानसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित रहे। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोधस्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया- एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। परन्तु, विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल हैं। आगामी मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा।

अवैध आव्रजन

अमेरिका में 6.80 लाख अनधिकृत भारतीय ट्रंप प्रशासन ने दिया अंतिम निष्कासन का आदेश

18 हजार और भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है अमेरिका

एजेंसी | वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अवैध आव्रजन के खिलाफ कार्रवाई तेज होने से अमेरिका में बिना वैध दर्जे के रह रहे भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई के नवंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 17,940 भारतीय ऐसे गैर-हिरासती मामलों में दर्ज थे, जिनके खिलाफ अंतिम निष्कासन आदेश जारी हो चुका था। यह संख्या अमेरिका में रह रहे सभी अनधिकृत भारतीयों की नहीं, बल्कि उन लोगों की है, जिनके मामलों में निष्कासन का अंतिम आदेश हो चुका है। प्यू रिसर्च सेंटर के संशोधित अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2023 में अमेरिका में करीब 6.80 लाख अनधिकृत भारतीय प्रवासी रह रहे थे। इस सूची में मैक्सिको पहले स्थान पर था, जबकि ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और होंडुरास के बाद भारत पांचवें स्थान पर था। 17,940 और 6.80 लाख के आंकड़ों को एक नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहला आंकड़ा अंतिम निष्कासन आदेश वाले भारतीयों का है, जबकि दूसरा अमेरिका में रह रहे कुल अनुमानित अनधिकृत भारतीय प्रवासियों का। ट्रंप प्रशासन ने आईसीई की गिरफ्तारी, हिरासत और डिपोर्टेशन क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक योजना तैयार की है।

क्या अपील और वकील का अधिकार खत्म हो गया?

यह कहना सही नहीं है कि हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को अपील, सुनवाई या वकील से संपर्क का कोई अवसर नहीं मिलता। अंतिम निष्कासन आदेश वाले मामलों में कानूनी प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी हो सकती है, जबकि कुछ मामलों में त्वरित निष्कासन प्रक्रिया लागू होती है। अमेरिकी सरकार अपने खर्च पर वकील देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन संबंधित व्यक्ति निजी वकील रख सकता है। पात्रता होने पर वह शरण, निष्कासन पर रोक या यातना-विरोधी संरक्षण की मांग भी कर सकता है। आईसीई के नियम बंदियों को कानूनी सामग्री और वकीलों से संपर्क की सुविधा देने की बात कहते हैं। हिरासत केंद्रों की परिस्थितियों को लेकर गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की रिपोर्ट में टेक्सास स्थित कैंप ईस्ट मोंटाना में मारपीट, चिकित्सा सुविधा की कमी, खराब भोजन और वकीलों तथा परिजनों से संपर्क में बाधा के आरोप लगाए गए। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।